

सच्चाई के दम पर  
जोश के साथ...मूल्य:  
₹ 02

# स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र



शुभमन  
गिल  
की भारतीय  
टीम के 37वें  
टेस्ट क्लब  
में हुई एंट्री

कानपुर, सोमवार, 26 मई, 2025  
वर्ष: 02, अंक: 147, पृष्ठ: 8+4

इनसाइड

पेस्टीसाइड दुकानदार की हथगोला मारकर हत्या » Pg11

» Pg06

# यूपी में सेमी फाइनल की तरह होंगे 2026 में पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश में दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम

» चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही अधिसूचना जारी करने की संभावना है

» लखनऊ/स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे आने के बाद ही प्रदेश की सियासी तस्वीर साफ होगी। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही अधिसूचना जारी करने की संभावना है।

ऐसे में राजनीतिक दल भी अपनी-अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। पंचायत चुनाव से न केवल दलों की लोकल पकड़ का पता चलेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनकी रणनीतियों की दिशा भी तय होगी। उत्तर प्रदेश के गांवों में पंचायत चुनाव को लेकर जो सरगर्मी दिख रही है, उससे यह साफ हो गया है कि ये चुनाव प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। लगभग 57,691 ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, 826 ब्लॉक प्रमुख, 3,200 जिला पंचायत सदस्य और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए करीब 1.27 लाख सीआर1 ग्रेड की मतपेटियों की खरीद के लिए ई-टेंडर भी जारी कर दिया है।

पिछले चुनाव अप्रैल-मई 2021 में हुए थे, इसलिए इस बार चुनाव की अधिसूचना जनवरी या फरवरी 2026 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव तीन स्तरों पर होते हैं - ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा और सियासी रसगुल्ले गांव के प्रधान चुनाव को लेकर होती है, क्योंकि ग्राम प्रधान सीधे गांव की



राजनीति पर प्रभाव डालते हैं।

गांवों में बिछ रही बिसात...

पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी दल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण के बाद किस सीट पर कौन उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। आरक्षण के बाद उम्मीदवारों की संभावनाओं का आकलन करना जरूरी होता है ताकि सही रणनीति बनाई जा सके। बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी होर्डिंग-पोस्टर के जरिए अपनी दावेदारी जताने लगे हैं। नेताओं और निर्वाचन आयोग की इस सक्रियता से साफ है कि पंचायत चुनाव को लेकर सियासी मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है।

पिछले पंचायत चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि पंचायत चुनावों में सत्ताधारी दल का ही दबदबा रहता है। 2021 के पंचायत चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, आम आदमी पार्टी और कई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। कुल 3050 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी खासा दम दिखाया। भाजपा ने 768 सीटें जीतीं, सपा ने 759, बसपा ने 319, कांग्रेस 125, आरएलडी 69 और आम आदमी पार्टी 64 सीटों पर जीत हासिल की। निर्दलीयों की संख्या 944 रही। भाजपा ने निर्दलीयों को अपने साथ जोड़कर 67 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर ली, जबकि सपा महज पांच जिलों में ही अध्यक्ष बना सकी। यह आंकड़ा यह बताता है कि पंचायत स्तर पर भी सत्ता का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है।

लगभग दो तिहाई विधानसभा सीटें

ग्रामीण इलाकों से आती हैं

पंचायत चुनावों को 2027 के विधानसभा



चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी संख्या की सीटें शामिल होती हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग दो तिहाई विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों से आती हैं, इसलिए पंचायत चुनाव का नतीजा सीधे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ताकत पर प्रभाव डालता है। पंचायत चुनावों में जो दल सफल होता है, उसके पास ग्रामीण वोट बैंक की मजबूत पकड़ होती है, जो आगे जाकर विधानसभा चुनावों में मददगार साबित होती है। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर हर जिले, क्षेत्र और जाति के हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद गहन मंथन करते हैं। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय ताकत, वोट प्रतिशत, पिछली बार की तुलना में वोटों में बढ़ोतरी या कमी, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाते हैं। ये चुनाव दलों को अपनी ताकत को सही आंकने का मौका देते हैं ताकि वे कमजोर हिस्सों पर काम कर सकें। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मतों की तुलना कर दल अपने वोट बैंक में आए बदलाव का आकलन करते हैं।

फिर इसके आधार पर उम्मीदवार चयन, गठबंधन और प्रचार रणनीति को दुरुस्त करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में पंचायत चुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इससे दलों की लोकल स्तर पर पकड़ का पता चलता है। पंचायत चुनाव से पार्टी का बूथ स्तर तक संगठन मजबूत होता है। गांवों के छोटे-छोटे चुनाव भी बड़े चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिस पार्टी के पास मजबूत ग्राम स्तर की पकड़ होती है, उसके लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतना आसान होता है। इसलिए दल पंचायत चुनाव को हल्के में नहीं लेते और पूरे जोर-शोर से चुनाव लड़ते हैं।

दबाव बनाने के लिए अपना दल पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगा !

इन चुनावों में अपना दल (एस) का भी विशेष महत्व है, जो बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में काम करता है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में घोषणा की है कि उनका दल यूपी पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि कोई गठबंधन नहीं होगा और अपना दल (एस) पूरी ताकत से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल है। उनका मानना है कि पंचायत चुनाव में अपनी ताकत आजमाकर वे आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति मजबूत करेंगे।

लेकिन पंचायत चुनावों में वह हमेशा अकेले ही चुनाव लड़ता रहा है। 2021 में भी अपना दल (एस) अकेले ही जिला पंचायत सदस्य चुनाव में हिस्सा लिया था। इस बार भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी और अपना दल (एस) साथ हैं, लेकिन गांवों में पंचायत चुनाव में वे एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी बनेंगे।

अनुप्रिया पटेल ने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहते हैं। गठबंधन में रहते हुए यह संभव नहीं था कि सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ पाएं, इसलिए अकेले चुनाव लड़ना जरूरी था। उन्होंने कहा कि संगठन को पंचायत चुनाव के अनुसार मजबूत करना होगा। पंचायत चुनाव में हर स्तर पर संगठन को तैयार करने की कवायद चल रही है। पार्टी बूथ स्तर पर भी मजबूत हो रही है ताकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पूरी मदद मिल सके।

# पंचायत चुनावों की आहट गांवों में शुरू हो गई राजनीति

रिजवान कुरैशी/ स्वराज इंडिया

**बिल्हौर।** पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही दावेदारों ने दुआ सलाम तेज कर दी है। अधिकांश दावेदारों ने अपना काम धंधा छोड़कर वोटों के बीच ही समय गुजारना शुरू कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई ग्रुप बन गए हैं। सबसे अधिक चर्चा नानामऊ ग्रामसभा की है। यहां की प्रधानी लंबे समय से राजनीतिक रंग में रंगती चली आ रही है। जिसके वजह विभिन्न पार्टियों के दावेदार सक्रिय नजर आ रहे हैं।

गौरतलब है कि अगले वर्ष 2026 के फरवरी मार्च महीने में पंचायत चुनाव होने हैं। शासन स्तर पर मतपेटियों के टेंडर से लेकर गांव सभा के परिसीमन तक तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगरीय निकायों के विस्तार के चलते कई गांवों का नक्शा बदल गया था। जिसके चलते कई छोटे गांवों का बड़ी गाँवसभाओं में विलय करने की चर्चा है। जिससे छोटे गांवों के प्रधानों के चेहरों के रंग उड़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर लंबे समय

» अधिकांश दावेदार काम धंधा छोड़ वोटों को दे रहे समय

» परिसीमन से कई गांवों का मिट सकता या अस्तित्व

» सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं कई ग्रुप

» लंबे समय से प्रधानी की मलाई काट रहे दावेदारों की सक्रियता बढ़ी



से प्रधानी की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्हें अब ज्यादा मलाई मिलने की उम्मीद जग गई है। जिस तह से पांच जून तक प्रक्रिया पूरी करने

चर्चित महिगावां सीट पर लगी हैं सबकी निगाहें

**बिल्हौर।** माहिगावां ग्रामसभा का चुनाव पिछली बार काफी रोमांचक रहा था। इस सीट से बार एसोसिएशन बिल्हौर के पूर्व अध्यक्ष और नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके एक प्रभावशाली व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इसमें उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था। इससे पहले वे निर्विरोध प्रधानी पा गए थे। लेकिन इस चुनाव में उनका बेटा नहीं जीत पाया था। अबकी बार चर्चा है कि क्या दोनों दावेदार फिर से आमने सामने आयेंगे। या फिर कोई तीसरा मैदान में उतरेगा और राजनीति के यह दोनों धुरंधर लोग उसे सपोर्ट करेंगे। फिलहाल यह तो समय ही तय करेगा।

का शासनादेश जारी हो गया है। उससे प्रधानों में हड़बड़ाहट की स्थिति है। ऐसे में मानक पूरा न करने वाली कई ग्राम सभाओं के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं कई नई ग्राम सभाओं की लाटरी खुलने की आस भी जाग गई है। पंचायतों का कार्यकाल अगले वर्ष मई महीने में पूरा हो रहा है। ऐसे में मई 2026 से पहले

नानामऊ जिला पंचायत सीट से कई ठोंक रहे ताल

**बिल्हौर।** नानामऊ जिला पंचायत सीट पर कई दावेदार अभी से चुनाव मैदान में ताल ठोंकते दिख रहे हैं। सपा समर्थित गगन सिंह निवर्तमान सदस्य हैं। वहीं कस्बे के लोकेश अवस्थी भी इस सीट पर अपनी नजर गढ़ाए हुए हैं। वहीं शिक्षक कुलदीप यादव भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही रचना सिंह के करीबी माने जाते हैं ऐसे में यह तो समय ही तय करेगा कि रचना सिंह किसके साथ खड़ी होंगी या वह चुप्पी साध जाएंगी।

चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी है। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य भी करीब छह महीने में पूरा हो पाता है। यही वजह है कि शासन स्तर पर तैयारियां शुरू होते ही गांवों में भी अड्डेबाजी और चुनावी चखचख शुरू हो गई है। बिल्हौर देहात, नानामऊ, मकनपुर, उत्तरी, पूरा, ककवन, राधन, महिगावां आदि ग्राम सभाओं का काफी चर्चा है।

## कानपुर: बर्ड फ्लू के खतरे को भांपते हुए चिड़ियाघर पहुंचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**कानपुर।** प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। नियमित दवाओं का छिड़काव करने के साथ ही पक्षियों, शेर और बाघ के बाड़े पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। पिछले दिनों बर्ड फ्लू को लेकर चर्चा में आए चिड़ियाघर का रविवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अनुराधा वेमुरी व राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य सचिव नीरज कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने चिड़ियाघर के अस्पताल, भंडारण गृह, झील को भी देखा। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने, नियमित रूप से दवाओं का छिड़काव करने, वन्यजीवों के व्यवहार पर नजर रखने को कहा। यह भी निर्देश दिया कि जैसे ही बर्ड फ्लू की रिपोर्ट आती है, उन्हें सूचित करें।



पक्षियों के साथ शेर व बाघों के बाड़ों पर दिया। उन्होंने पूछा की कोई पक्षी मृत तो नहीं पाया गया है। सभी पशु-पक्षियों की नियमित जांच की जाए।

अगर किसी वन्यजीव के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दें, खाना कम खाए तो उसे तत्काल आइसोलेट करने को कहा।

साथ ही उसके नमूनों की जांच भी की जाए। जिन बाड़ों में पक्षी हैं, वहां के तालाब की नियमित रूप से सफाई भी कराई जाए। अधिकारियों को जानकारी दी गई कि शुरुवार को एक नीलगाय के बच्चे की भी आपस में लड़ाई के दौरान घायल होने के बाद मौत हो गई।

उसके नमूने भी एहतियात के तौर पर जांच के लिए भेजे गए हैं। चिड़ियाघर की निदेशक श्रद्धा यादव ने बताया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव के निर्देशानुसार सतर्कता बढ़ा दी गई है। बताया कि राष्ट्रीय उच्च पशु रोग संस्थान भोपाल को भेजे गए वन्यजीवों के नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

**9 पशुओं के लिए गए सैंपल**

बर्ड फ्लू से बचाव के लिए रविवार को पशुपालन विभाग की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों के 9 सैंपल लिए गए। जिसे जांच के लिए बरेली भेज दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जनपद में कहीं भी पक्षियों की अस्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है। साथ ही किसी पोल्ट्री या पोल्ट्री उत्पाद के विपणन व आवागमन पर जिला प्रशासन ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

# ‘गालीबाज नर्सिंग सिस्टर’ से हर कोई हैरान-परेशान!

» आजाद नगर ईएसआई चेरुट हॉस्पिटल में तैनात दबंग नर्सिंग सिस्टर रीता वर्मा की करतूत उजागर

» मैट्रन से लेकर सीएमएस तक लगा चुकी है निदेशक से गुहार

» कार्रवाई के तहत सर्वोदय नगर अस्पताल से पिपरी सोनभद्र किया गया था ट्रांसफर, जुगाड़ से आजाद नगर में है तैनात

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया कानपुर। जैसे तो हर सरकारी कर्म के शालीनता और सभ्य आचरण को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार कर्मचारी आचरण नियमावली का पाठ पढ़ाती रहती है लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सरकारी कार्यालय और संस्थान हैं जहां पर कर्मचारी दबंगई से काम करते हैं। ताजा प्रकरण कानपुर महानगर के केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के अधीन आने वाले आजादनगर ईएसआई चेरुट हॉस्पिटल का है। यहां पर तैनात एक दबंग नर्सिंग सिस्टर की करतूत से हर कोई परेशान और हैरान है वयों कि वह मैटर्न से लेकर सीएमएस तक से अमद्रता व अनुशासनहीनता कर चुकी है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से उसके हौसले बुलंद हैं।

कानपुर के आजादनगर ईएसआई चेरुट हॉस्पिटल की ओर से निदेशक को भेजे गए एक पत्र के अनुसार रीता वर्मा जो कि परिचारिका-नर्सिंग सिस्टर के पद पर तैनात हैं। उनका कार्य व्यवहार ऐसा है कि पूरा अस्पताल दुःखी है। वह बिना बताए ड्यूटी से अचानक चली जाती हैं और सीनियर्स को बिना बताए सरकारी दस्तावेजों के फोटो और वीडियो खींचती हैं। आरोप हैं कि कई बार शाम की ड्यूटी में साइन करके चली जाती हैं, मरीज बुलाते रहते हैं लेकिन वह नहीं आती है। डॉक्टरों के फोन करने पर बड़ी मुश्किल से आती हैं। इस पर जब वहां की मैटर्न सरिता ने इसको लेकर आपत्ति जताई तो रीता वर्मा ने धमकाया कि कुछ नहीं कर पाओगी, कहा कि ‘मैं सबको देख लूंगी...।’ इसके अलावा वहां पर काम करने वाली अन्य सिस्टर और कार्मिकों से गाली देकर

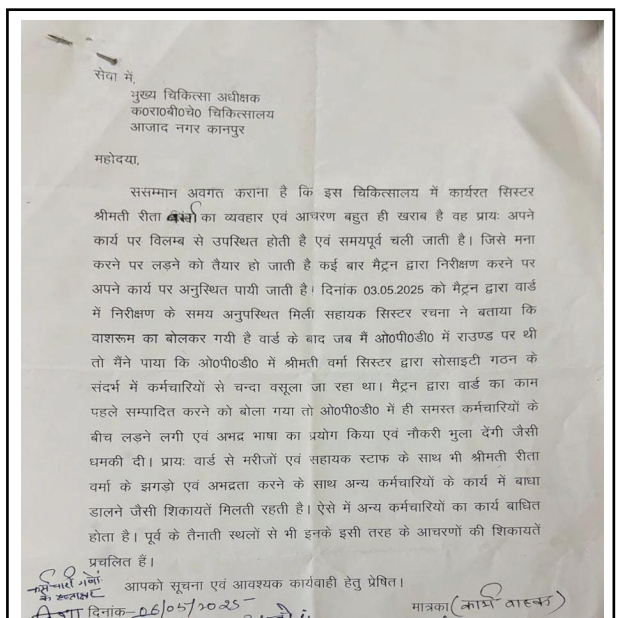


आरोपी नर्सिंग सिस्टर रीता वर्मा



प्रमुख सचिव

बात करती है और कहती हैं कि ‘जो बोलेगा उसको जूतों से मारूंगी’ वहां के कर्मियों के आरोप हैं कि वह एससी-एसटी उत्पीड़न के झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी भी देती है। इससे कर्मचारी दहशत में रहते हैं। अभी हाल में ही इनके कृत्यों को लेकर इनसे स्पष्टीकरण तलब किया गया था लेकिन कोई जबाब तक नहीं दिया। कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता करने पर बीते वर्ष चिकित्सालय सर्वोदयनगर कानपुर से हटाकर सोनभद्र जिले के पिपरी स्थित अस्पताल में तैनात कर दिया गया था लेकिन शासन में जुगाड़ लगाकर कानपुर में आजाद नगर अस्पताल से संबद्ध हो गई। रीता वर्मा ने अब आजादनगर अस्पताल का माहौल खराब कर दिया है। इससे अन्य कार्मिक परेशान हैं।



## रीता वर्मा की शिकायतों पर निदेशक मौन

नर्सिंग सिस्टर रीता वर्मा के कृत्यों की जानकारी कानपुर में बैठे निदेशक एसपी सिंह को कई बार लिखित और मौखिक रूप से दी गई लेकिन वह शासन संबद्धता होने की बात कहकर किनारा कर लेते हैं। कई बार तो कुछ न कुछ मजबूरियां बताकर मौन साध लेते हैं। इसकी वजह से नर्सिंग सिस्टर बेलगाम होकर विभाग में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। जैसे भी ईएसआई अस्पतालों की हालत खस्ताहाल है, वहां पर इलाज के नाम पर क्या हो रहा है, सभी को पता लेकिन कुछ ऐसे कर्मियों की वजह से रही सही कसर भी पूरी हुई जा रही है। इस प्रकरण को लेकर निदेशक एसपी से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि निदेशक अगले माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए ज्यादा रूचि नहीं ले रहे हैं।

प्रकरण की जानकारी करेंगे, एक नर्सिंग सिस्टर ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी संबद्धता को लेकर भी जांच कराएंगे, शिकायतों के बाद भी कैसे वहां भेज दिया गया है। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

डॉ.एमके शन्मुगा सुंदरम  
प्रमुख सचिव, श्रम एवं  
सेवायोजन विभाग  
उत्तर प्रदेश

# भाजपा सांसद को गाली देने वाला चपरासी, ब्लॉक प्रमुख का करीबी

» पुलिस सूत्रों के मुताबिक चपरासी की आखिरी लोकेशन लखनऊ में मिली

» चपरासी की वायरल हुई 23 मिनट 25 सेकेण्ड की ऑडियो रिकार्डिंग में वह भाजपा सांसद को दे रहा है गालियां

» ऑडियो के आखिरी में ब्लॉक प्रमुख बुला रहे चपरासी को चाय पर

## मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

**कानपुर।** शुरुवार को सोशल मीडिया पर प्रचलित हुए ऑडियो रिकार्डिंग में एक भाजपा सांसद को गाली देने वाला चपरासी राहुल शुक्ला पुलिस के डर से जिला छोड़ गया है। पुलिस उसकी तलाश में उसके कई ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को चपरासी की लास्ट लोकेशन राजधानी लखनऊ में मिली। जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस की दो टीमों लखनऊ में उसकी तलाश करने पहुंची।

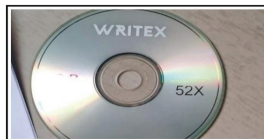
चौबेपुर थाना क्षेत्र के बोझा निवासी नागेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सत्येन्द्र सिंह ने शिवराजपुर पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 23/05/2025 को रात्रि में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो

## आरोपित चपरासी की तलाश में पुलिस ने कई जगह दी दबिश

### जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऑडियो प्रचलित, जांच शुरू

» बीएसए ने आनन फानन जारी किया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का निलंबन आदेश

» सपा सरकार की राज्यमंत्री का करीबी बताया जा रहा है राहुल शुक्ला



**स्वराज इंडिया संवाददाता बिल्हौर (कानपुर)।** एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व उनके एक समर्थक के खिलाफ अनाद बातचीत का ऑडियो शुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है। ऑडियो की आवाज मिलान कर बेसिक शिक्षा विभाग के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गिरफ्तार कर दिया गया है। वहीं एक गान प्रधान को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की।

जानकारी के मुताबिक बिल्हौर में शुरुवार को एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ अभद्र भाषा

प्रयोग करने का ऑडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हुआ। इसमें बातचीत करने वाले व्यक्ति की आवाज का मिलान कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि ऑडियो कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है। मामले में उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरा प्रथम में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत कर्मचारी राधन गांव निवासी राहुल शुक्ला की तलाश शुरू की गई है। उसके खिलाफ बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने बिना देर किए निलंबन की कार्रवाई कर दी है। और उसे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हौर से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं इस कार्रवाई को राजनीतिक चरम से भी देखा जा रहा है। जिसकी वजह राहुल शुक्ला की सपा शासन में राज्यमंत्री रही अरुणा कोरी से निकटता मानी जा रही है।

लगभग 23 मिनट 25 सेकेण्ड की है। ऑडियो रिकार्डिंग सुनी। जिसमें राहुल शुक्ला पुत्र हरदत्त शुक्ला निवासी राधन थाना शिवराजपुर व शुभम बाजपेई पुत्र अज्ञात निवासी काकुपुर रबन के मध्य वार्ता हो रही है। जिसमें राहुल शुक्ला ने बिल्हौर क्षेत्र के कई संभ्रांत व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों सहित मेरा नाम लिया है। समस्त क्षत्रिय समाज के लिए बेहद गंदी गालियों का कई बार प्रयोग करते हुए सुनाई दे रहा है व एक किसी व्यक्ति को गायब कर दूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा।

### बयान

मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है, मेरी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए इस तरह साजिश की जा रही है। मैं पुलिस में शिकायत करूंगा।

शुभम बाजपेई,  
ब्लॉक प्रमुख शिवराजपुर

उपरोक्त राहुल शुक्ला शातिर किस्म का आदमी है जिस पर आपराधिक मुकदमें पजीकृत हैं। इसका क्षेत्र में पूर्व से ही काफी भय व दहशत व्याप्त है। जान से मारने की व हत्या करने की धमकी दे रहा है जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपित चपरासी की तलाश में कई टीमों गठित की गई हैं। यह टीम चपरासी राहुल की तलाश में जुटी हैं। सूत्रों की मानें तो पुलिस के राडार पर वह लोग भी हैं। जिन्होंने राहुल शुक्ला को भगाने में मदद की है।

### प्रमुख जी ने चाय पर भी बुलाया

कानपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरा प्रथम में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत कर्मचारी राधन गांव निवासी राहुल शुक्ला और शिवराजपुर ब्लॉक प्रमुख शुभम बाजपेई से 23 मिनट 25 सेकेण्ड की हुई बातचीत में राहुल कई दफा सांसद समेत कई लोगों को गरिया रहा है। जिसमें ब्लॉक प्रमुख जी हॉ में हॉ मिला रहे हैं साथ ही एक बार ठहाके मार के हंसे भी और ऑडियो के लास्ट में ब्लॉक प्रमुख जी आरोपित को चाय की दावत दे रहे हैं। इसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम है। वहीं उनकी सादगी भरी बातें और सम्मान देना भी लोगों के जेहन में है। लेकिन जब ऑडियो की जांच होगी तो गवाह वह भी बनेंगे।

## गायब हुई किशोरी केस में सनसनीखेज मोड़, शादी की फोटो आई सामने

### शिवांक अग्निहोत्री स्वराज इंडिया

**कानपुर।** देहात रनिया थाना क्षेत्र में बीते 18 मई से लापता 16 वर्षीय किशोरी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस किशोरी को परिजनों ने गांव के ही सुनील यादव समेत पांच युवकों पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था, उसकी एक फोटो सामने आई है जिसमें वह कथित मुख्य आरोपी सुनील यादव के साथ विवाह की मुद्रा में नजर आ रही है। जिसने इस केस को एक नया और सनसनीखेज मोड़ दे दिया है। कानून के अनुसार, चूंकि किशोरी नाबालिग है, इसलिए यह शादी अवैध मानी जाएगी और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आती है।

सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि आरोपी खुलेआम शादी कर फोटो खिंचा रहा है, तो पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? इससे पहले पीड़िता के परिजन दो बार एसपी और एडिशनल एसपी से मिल चुके हैं, लेकिन रनिया पुलिस की निष्क्रियता और संवेदनहीनता अभी भी बनी हुई है।

नौबस्ता की घटना से सबक नहीं, ऐसे ही

» फोटो में आरोपी के साथ नजर आई नाबालिग, दो महीने पहले नौबस्ता में ऐसा ही मामला बना था मानव तस्करी का शिकार

» रनिया केस में पुलिस की निष्क्रियता पर उठे सवाल, आरोपी के साथ फोटो से उभरा नया मोड़



### मामले में किशोरी की हुई थी तस्करी

इस तरह के मामलों में प्रशासन की लापरवाही पहले भी भयावह नतीजे दे चुकी है। महज दो महीने पहले कानपुर नगर के नौबस्ता थाना

क्षेत्र में भी एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।

परिजनों के विरोध के बावजूद युवक ने किशोरी से विवाह किया और कुछ समय बाद वह उसे मानव तस्करों के हाथों बेचकर फरार हो गया। वह मामला भी ठीक इसी पैटर्न पर घटित हुआ था—नाबालिग को बहला-फुसलाना, शादी का झांसा, और फिर अंत में मानव तस्करी का जाल। अब रनिया का मामला भी उसी दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। यदि पुलिस समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं करती, तो यह मामला भी किसी बड़े अपराध की नींव बन सकता है।



सम्पादकीय

वैश्विक प्रयासों से रुकेंगे संगठित अपराध

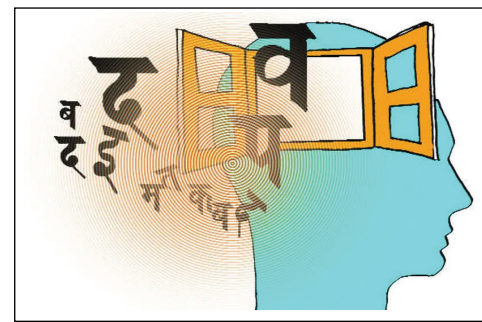
यह खबर परेशान करने वाली है कि म्यांमार और पूर्वी एशिया के कई देशों से जो संगठित साइबर अपराध संचालित हो रहे हैं, उनके चंगुल में बड़ी संख्या में भारतीय युवा भी हैं। हाल ही में म्यांमार के दुर्गम इलाकों में बनाये गए साइबर अपराधियों के अड्डों से सत्तर भारतीय युवाओं को छोड़ा गया है। जिनको डरा-धमकाकर भारत में साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिये इस्तेमाल किया जाता था। बताया जाता है साल 2022 के बाद म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया आदि से छह सौ से अधिक भारतीयों को अपराधियों के चंगुल से बचाया जा चुका है। आशंका है कि कई हजार भारतीय युवा म्यांमार समेत विभिन्न देशों में साइबर अपराधियों के अड्डों में जबरन रोके गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय युवा प्रतिभाएं दलालों की साजिश से संगठित साइबर अपराध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के चंगुल में फंस जाती हैं। विडंबना ही है कि हम अपने युवाओं को न तो रोजगार दे पा रहे हैं और न ही विदेशों में अपना भविष्य संवारने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं को फर्जी एजेंटों के चंगुल से बचा पा रहे हैं। आखिर हमारी एजेंसियां ऐसी धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही हैं। हाल के दिनों में कई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि युवा अपनी जमीन बेचकर व कर्ज उठाकर विदेश जाते हैं, लेकिन एजेंटों की धोखाधड़ी से वे साइबर अपराधियों के शिकंजे में फंस जाते हैं। दरअसल, साइबर अपराधियों का

मकड़जाल इतना मजबूत हो चुका है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उन पर नियंत्रण कर पाना संभव न होगा। ऐसे वक्त में जब साइबर अपराधियों का नेटवर्क दुनिया की आर्थिकी को चूना लगा रहा है, मिल-जुलकर इनके खिलाफ अभियान चलाना वक्त की जरूरत है। निश्चित रूप से यह एक विकट संकट है, जिसे दुनिया के देशों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह जानते हुए कि साइबर अपराधियों का संगठन लगातार ताकतवर होता जा रहा है और वे समानांतर काली अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। दरअसल, हो यह रहा है कि देश-दुनिया में ऑनलाइन फॉंड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वे सुनहरे सपने दिखाकर बेरोजगार युवाओं को फंसाते हैं। उन्हें जगह कोई और बतायी जाती है और अंततः साइबर अपराधियों के अड्डों पर पहुंचा दिया जाता है। युवाओं के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। हाल ही में जिन सत्तर भारतीयों को म्यांमार में साइबर अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया गया, उसमें म्यांमार के सीमा सुरक्षा बल की बड़ी भूमिका रही है। इन मुक्त कराए गए भारतीयों में पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी व राजस्थान आदि राज्यों के लोग थे। इसी तरह म्यांमार व अन्य पूर्वी एशिया के देशों में साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसे हुए भारतीयों को मुक्त कराने के लिए इन देशों की सरकारों से सहयोग मांगा जाना चाहिए।

नेताओं को बौना बना रही है संकीर्णता

विश्वनाथ सचदेव

मूल जाना आदमी की फितरत है। आदमी अच्छी बातें भी मूल जाता है, और बुरी बातें भी। बुरी बातों को मूल जाना तो अच्छी बात है, पर कुछ अच्छी बातों को मूल जाना अच्छा नहीं है। ऐसी ही अच्छी बात वर्ष 1965 की भारत-पाक लड़ाई है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। पता नहीं कितनों को याद होगा कि उस लड़ाई में अब्दुल हमीद नाम का एक भारतीय सैनिक भी था, जिसने पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करके हमारी जीत को संभव बना दिया था। तब कर्नल मास्टर अब्दुल हमीद ने हमें जिता तो दिया, पर अपनी जान की कीमत देकर। कृतज्ञ राष्ट्र ने उस जांबाज शहीद को मरणोपरान्त परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। इस शहीद का जन्म उत्तर प्रदेश के दुल्लहपुर नामक गांव में हुआ था।



दशकों में न जाने कितनी जगह के नाम बदले गये हैं। ज्यादातर नाम मुसलमानों के हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। औरंगजेब ने भले ही अत्याचार किये हों, पर वह वर्षों तक इस देश में शासन करता रहा, यह हकीकत तो अपनी जगह है। फिर, हम क्यों भूल जाते हैं कि किसी औरंगजेब को याद करने का मतलब उन अत्याचारों की भी याद दिलाता है, जिनसे हमारे इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। ऐसी बातों को याद रखना इसलिए भी जरूरी है कि इन्हें दुहराया न जाये। बहरहाल, जगहों के नाम बदलना कोई नयी बात नहीं है। पर इस प्रक्रिया के पीछे की मानसिकता को भी समझा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शहरों आदि के नाम बदलने का काम सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही हो रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, द्रमुक आदि पार्टियों ने भी अपने-अपने शासन काल में इस तरह नाम बदले हैं। सच्चाई यह है कि अक्सर यह बदलाव राजनीतिक स्वार्थ का परिणाम होते हैं। अपने-अपने हितों के लिए हमारे राजनीतिक दल अक्सर जगहों का नाम बदलना एक आसान मार्ग समझ लेते हैं। लेकिन, यह आसान मार्ग अक्सर राष्ट्रीय हितों से भटका देता है, इस बात को भुलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की जो कवायद इस समय चल रही है वह उन सबके लिए चिंता का विषय होनी चाहिए जो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। सन 2012 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के नाम बदले गये थे।

गांव वालों ने अपने इस सपूत के सम्मान में गांव के स्कूल का नाम वीर अब्दुल हमीद उच्च प्राथमिक विद्यालय रखा था। बरसों से यह नाम गांव की एक पहचान बना हुआ था। कुछ ही अर्सा पहले स्कूल का नाम बदल दिया गया- नया नाम पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय धामपुर कर दिया गया। क्यों बदला गया, किसी ने नहीं बताया। बस बदल दिया! नाम बदलने की यह अकेली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मऊ को जोड़ने वाली सड़क पर बने एक द्वार का नाम ऐसे ही बदल दिया गया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाम का यह द्वार बुलडोजर चला कर गिरा दिया गया। मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर बने एक कॉलेज की दीवारें गिरा देने वाला समाचार भी हाल ही का है। यह बात भुला दी गयी कि मुख्तार अहमद अंसारी कभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आजादी की लड़ाई के दौरान यह पद संभालने वाले अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की नींव रखने वालों में थे। नाम बदलने का यह सिलसिला अब नया नहीं लगता। चौंकाता भी नहीं। पिछले दो

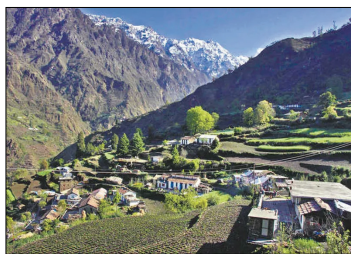
बढ़ गया है विसंगतियों को प्रश्रय का खतरा

उत्तराखंड में नया भूमि कानून

जयसिंह रावत

अब तक गैर-कृषक के लिये जमीनों की खरीद पर बंदिशें थीं, लेकिन अब जिसकी भी उत्तराखंड में अचल सम्पत्तियां हैं उनके लिये भी किसानों की जमीनें खरीदने का रास्ता निकल गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने नया भूमि कानून पास तो करा दिया है, लेकिन इस कानून से पहाड़वासियों की नाउम्मीदी ज्यादा बढ़ गयी है। सरकारी पक्ष नये कानून को सख्त बचाकर प्रचारित कर रहा है, लेकिन गरीब कास्तकारों के पुरखों की जमीनों के भू-खोरों, धनासेतों और गैर-कृषकों द्वारा हड़पने के नये रास्ते खुले बताते हैं।

हालांकि, किसी देशवासी के लिये बाहरी शब्द का प्रयोग उचित नहीं है फिर भी जिन लोगों को बाहरी माना जा रहा है, उनके लिये उत्तराखंड में जमीनें खरीदने के लिये पिछले दरवाजे खुले हैं। अब तक गैर-कृषक के लिये जमीनों की खरीद पर बंदिशें थीं, लेकिन अब जिसकी भी उत्तराखंड में अचल सम्पत्तियां हैं उनके लिये भी किसानों की जमीनें खरीदने का रास्ता निकल गया है मगर नगर निकाय चाहे कहीं की भी हों, उन्हें इस कानून से मुक्त कर दिया। विधि विशेषज्ञ और भू-कानून के लिए आन्दोलन करने वाले इसे प्रदेश की जनता के साथ छलावा बता रहे हैं। नये कानून की धारा दो में कहा गया है कि 'नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, छावनी



परिषद क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय-समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह कानून सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लोग गांव छोड़कर आसपास के कस्बों में बहुत तेजी से बस रहे हैं इन्हीं नगरीय क्षेत्रों में भूमि की सर्वाधिक खरीद-फरोख्त होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उद्यान, पर्यटन, के लिये निजी न्यास, संस्था, कम्पनी, फर्म, पंजीकृत सहकारी

संस्था आदि के लिए भूमि का अन्तरण पर पहले भी प्रतिबंध नहीं था। नयी व्यवस्था में अगर भूमि का अन्तरण जनहित में है तो जमीन चाहने वालों का वास्तविक आंकलन कर भूमि अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। साथ ही अन्तरण अनुमति से पूर्व सम्बंधित विभागों द्वारा निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन तथा प्लांट और मशीनरी इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव का आंकलन करते हुए भूमि अनिवार्यता प्रमाणपत्र विभागाध्यक्ष या एक रैंक नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भूमि अन्तरण की अनुमति केवल हरिद्वार और उधमसिंह नगर में दी जायेगी। अगर भूमि की खरीद-फरोख्त की बंदिशें शेष 11 जिलों के लिये हैं तो

उन पहाड़ी जिलों के नगर निकाय क्षेत्र इन दो जिलों की तरह कानून से मुक्त क्यों कर दिये गये? नये कानून में व्यवस्था की गयी है कि अगर कोई व्यक्ति जो धारा 129 के तहत उत्तराखंड का खातेदार न हो तो उसे रजिस्ट्रार के सामने शपथपत्र देना होगा कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने आवासीय उद्देश्य के लिये अपने जीवनकाल में 250 वर्गमीटर जमीन नहीं खरीदी है। सरकार को शिकायतें मिली थीं कि कानून का दुरुपयोग करते हुए कुछ लोगों ने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी 250 वर्गमीटर जमीनें खरीद ली हैं। जबकि मूल कानून में व्यवस्था थी कि एक परिवार एक ही बार जमीन खरीद सकेगा।

# शुभमन गिल

## की भारतीय टीम के 37वें टेस्ट वलब में हुई एंट्री

शुभमन गिल 20 जून को जब सफेद टी-शर्ट के ऊपर नीले (नेवी ब्लू) रंग के कोट में इंग्लैंड के लीड्स मैदान पर टॉस के लिए उतरेंगे तो उनके पिता लखविंदर सिंह गिल और दादा दीदार सिंह का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा क्योंकि उन्हें वर्षों की मेहनत का सुखद फल मिलेगा। लखविंदर ने जब शुभमन के क्रिकेट कौशल को देखकर भारत और पाकिस्तान की सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर पंजाब के फाजिल्का जिले के अपने गांव चाख खेरा वाला से मोहाली जाने का फैसला किया तो उनके पास कोई दूसरी योजना नहीं थी। शुभमन

उस समय नौ साल के थे।

उन्होंने उस उम्र तक

सिर्फ एक ही

'खिलौना' खेला

था और वह था

उनके दादा से मिला

बल्ला।

गिल की कहानी अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प का पालन करने के बारे में ही है। इसके साथ ही यह एक ऐसे ही पिता की कहानी है जो अपने बेटे को भारतीय टीम में पहुंचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। शुभमन इंग्लैंड दौरे पर जब भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे तो यह लखविंदर के पिछले 16 साल की मेहनत का

परिणाम होगा। यह जरूरी नहीं कि खेल से जुड़ी सभी कहानियां सहानुभूति भरी हों। वे जब्बे, उत्कृष्टता के प्रति जुनून और वर्षों तक एक परिवार के रूप में किए गए त्याग की कहानियां भी हो सकती हैं। शुभमन के खेल में भटकने से रोकने के लिए परिवार कई वर्षों तक अपने 'कमफर्ट जोन' (आरामदायक स्थिति) से दूर रहा।

इसके साथ ही उसने पारिवारिक समारोहों से दूर रहने का फैसला किया।

शुभमन जब 2018 में अंडर-19 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे तब उनके पिता ने न्यूज एजेंसी से कहा था, 'हमने सालों तक किसी शादी समारोह में भाग नहीं लिया था ताकि हमारे बेटे का ध्यान क्रिकेट पर नहीं भटके।' इस बात में हालांकि कोई शक नहीं कि गिल के परिवार के पास शुरुआत से ही संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। उनके दादा दीदार अपने फाजिल्का स्थित घर के विशाल आंगन में एक अस्थायी पिच बनवा सकते थे और पिता चार लोगों के परिवार को चंडीगढ़ ले जाने का जोखिम उठा सकते थे।

हालांकि गांव में उनके आरामदायक जीवन से बहुत दूर था। गिल की कहानी सही समय पर सही जगह पर होने और अपने काम को सही से अंजाम देने का एक बेहतरीन उदाहरण है।

गिल के ख्वाबों को 2011 में उस समय उड़ान भरने का और बड़ा मौका मिला जब भारत के पूर्व तेज गेंदबाज करसन घावरी की नजर उन पर पड़ी। घावरी बीसीसीआई की मदद से पंजाब क्रिकेट संघ (पीसीए) के लिए आयोजित तेज गेंदबाजों की शिविर में गये थे। उन्हें वहां यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के खिलाफ बढ़िया तकनीक से बल्लेबाजी नहीं कर रहा था।

## परिवार का योगदान और मेहनत लाई रंग

घावरी इसके बाद अपने किसी सहायक के साथ पीसीए स्टेडियम के बाहर अंडर-14 स्तर का मैच देखने के लिए पहुंचे और वहां एक किशोर खिलाड़ी की तकनीक ने उन्हें काफी प्रभावित किया। वह उस लड़के के बारे में पता करने के लिए पास ही पेड़ की छाया में खड़े होकर पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देख रहे एक व्यक्ति के पास पहुंचे और पूछा, 'वह लड़का कौन है? कहाँ रहता है?' किसमत से वह लखविंदर थे जो अपने बेटे को बल्लेबाजी करते हुए देख रहे थे।

लखविंदर ने कहा, 'वह मेरा बेटा शुभमन है और वह 12 साल का है' भारत के लिए 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले घावरी ने इसके बाद उन्हें तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए शिविर में बुलाया। इस शिविर में 12 साल का यह खिलाड़ी संदीप शर्मा जैसे तत्कालीन भारत के अंडर-19 तेज गेंदबाजों का

डटकर सहजता से सामना करने में सफल रहा। घावरी की सिफारिश के बाद गिल को पंजाब अंडर-14 टीम में शामिल किया गया। भारतीय टीम जब 2018 दौरे के लिए इंग्लैंड जा रही थी जब एमएसके प्रसाद की चयन समिति ने टीम में अनमोलप्रीत सिंह को मौका देने का मन बनाया था लेकिन कोच राहुल द्रविड़ की अनुरोध पर गिल को चुना गया। प्रसाद ने कहा, 'हम उनकी मांग को टुकरा नहीं सके। शुभमन ने इसके कुछ महीने बाद अंडर 19 विश्व कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।' अनमोलप्रीत के पास रन थे लेकिन शुभमन के पास तकनीक और दबाव को झेलने वाला स्वभाव था। इस खेल के शीर्ष स्तर पर इन दोनों की गिनती रनों के बराबर होती है। द्रविड़ ने कुछ खास देखा था और वह नहीं चाहते थे कि यह लड़का घरेलू क्रिकेट में ज्यादा समय तक टिका रहे।



# ग्राम पंचायत-मकनपुर

## विकास खंड-बिल्हौर, जनपद -कानपुर नगर

पत्रांक- मेमों

दिनांक-26.05.2025

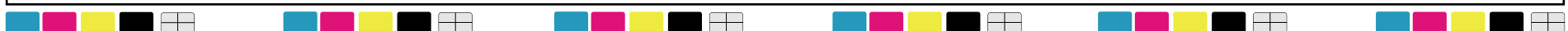
महामहिम राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम पंचायत मकनपुर, विकास खण्ड बिल्हौर के जी0एस0टी0 धारक ईट, ईट गिट्टी 40 एम0एस0 एवं अन्य जी0एस0टी0 धारक सामग्री विक्रेताओं से सीमेन्ट, बालू, मौरंग, पत्थर गिट्टी 20 एम0एम0, हयूम पाईप, टाइल्स आर.जी.एस.ए. के अन्तर्गत कराये जाने वाले निम्न कार्यो के कार्य स्थल पर सामग्री आपूर्ति हेतु दिनांक 29.05.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक निविदाये आमन्त्रित की जाती है। विक्रित निविदाये निविदा बाक्स में निर्धारित समय के अन्दर डाली जायेगी। निर्धारित समय सीमा के उपरान्त निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा प्रपत्र ग्राम पंचायत मकनपुर कार्यालय से दिनांक 27.05.2025 से दिनांक 28.05.2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस में मु0 200.00 नकद जमा कर प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाये दिनांक 29.05.2025 को अपरान्ह तीन बजे कार्यालय ग्राम पंचायत मकनपुर कानपुर नगर के कक्ष में उपस्थित सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। ग्राम पंचायत सचिव को यह अधिकार होगा किसी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

### अल्पकालिक निविदा सूचना

| सं. | कार्य का नाम                      | कार्य स्थल                               | अनुमानित लागत | सामग्री                 | कार्य अवधि |
|-----|-----------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------|
| 1-  | इंटरलॉकिंग निर्माण                | कुरैशी मस्जिद से छोटे लाल राठौर तक       | 4 लाख         | सीमेंट,मौरंग ई0 ईटा आदि | 1 माह      |
| 2-  | इंटरलॉकिंग निर्माण                | राजकुमार से आफाक तक                      | 4 लाख         | सीमेंट,मौरंग ई0 ईटा आदि | 1 माह      |
| 3-  | इंटरलॉकिंग निर्माण                | जयप्रकाश से रामचंद्र तक                  | 1.5 लाख       | सीमेंट,मौरंग ई0 ईटा आदि | 20 दिन     |
| 4-  | इंटरलॉकिंग निर्माण                | मशरूर खान से सलमा तक                     | 6.20 लाख      | सीमेंट,मौरंग ई0 ईटा आदि | 1 माह      |
| 5-  | इंटरलॉकिंग निर्माण                | बृजनंदन से सुभाष पाल तक                  | 1.17 लाख      | सीमेंट,मौरंग ई0 ईटा आदि | 20 दिन     |
| 6-  | इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण         | आभिर की दुकान से मदरसा चौ0 इतरत हुसैन तक | 3.34 लाख      | ईटा, मौरंग आदि          | 1 माह      |
| 7-  | इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण         | जाहिद हुसैन से आर0आर0सी सेंटर तक         | 4 लाख         | ईटा, मौरंग आदि          | 1 माह      |
| 8-  | खड़जा निर्माण                     | इमरान अली से जावेदुल हक तक               | 2.25 लाख      | ईटा, मौरंग आदि          | 20 दिन     |
| 9-  | खड़जा निर्माण                     | नबी अली से जियाउल अनवार तक               | 1.5 लाख       | बैटरी पैनल आदि          | 20 दिन     |
| 10- | खड़जा निर्माण                     | ताबीर अली से आरा मशीन के सामने तक        | 2.80 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 1 माह      |
| 11- | सौर्य ऊर्जा मरम्मत                | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर      | 2 लाख         | ईटा, सीमेंट आदि         | 1 माह      |
| 12- | नाली,मरम्मत क्रास व पट्टी निर्माण | ग्राम पंचायतो में विभिन्न स्थानों पर     | 1,28 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 13- | खड़जा निर्माण                     | तबीब आलम से अयान तक                      | 2.15 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 14- | खड़जा निर्माण                     | मो0मुशीर से नजीब अहमद के घर तक           | 2 लाख         | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 15- | नाली निर्माण                      | प्रवेश पाल से किशोर की दुकान तक          | 1.49 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 16- | नाली निर्माण                      | राज जी की दुकान से बाबू पाल तक           | 1.90 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 17- | नाली निर्माण                      | कुरैशी मस्जिद से जियानत हुसैन तक         | 1.90 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 18- | नाली निर्माण                      | सतार अहमद से रशीद खान तक                 | 1.90 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 19- | नाली निर्माण                      | असलम खान से मस्सू खान तक                 | 1.70 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 20- | कायाकल्प                          | प्राथमिक विद्यालय मकनपुर द्वितीय         | 2.50 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 21- | कायाकल्प                          | आंगनबाड़ी केन्द्रो पर कोतवाली पास        | 1.50 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 22- | खड़जा निर्माण                     | आंगनबाड़ी केन्द्रो पर कोतवाली पास        | 1.55 लाख      | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 23- | पंचायत भवन मरम्मत व रंगाई पुताई   | सादात हुसैन से मार्फत हुसैन के सामने तक  | 2 लाख         | ईटा, सीमेंट आदि         | 20 दिन     |
| 24- | कायाकल्प                          | प्राथमिक विद्यालय भागमलपुरवा             | 2 लाख         | ईटा, सीमेंट पेंट आदि    | 20 दिन     |
| 25- | रैन वाटर हार्वेस्टिंग             | आंगनबाड़ी केन्द्र नया वाल                | 1 लाख         | पाइप, सीमेंट ईटा आदि    | 20 दिन     |
| 26- | रैन वाटर हार्वेस्टिंग             | आंगनबाड़ी केन्द्रो पर                    | 2 लाख         | पाइप, सीमेंट, ईटा आदि   | 20 दिन     |
| 27- | समर सेविल व प्लंबरिंग             | प्राथमिक विद्यालय भागमलपुरवा             | 1.55 लाख      | मोटर, सीमेंट आदि        | 20 दिन     |

**मजाहिर हुसैन-ग्राम प्रधान मकनपुर**  
विकास खंड-बिल्हौर  
कानपुर नगर

**जितेन्द्र कुमार -ग्राम विकास अधिकारी**  
विकास खंड-बिल्हौर  
कानपुर नगर



# कानपुर में बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे ट्रक डंपर

स्वराज इंडिया  
**X कलूसिव**

निर्मल तिवारी/स्वराज इंडिया

**कानपुर।** एक तरफ ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शासन प्रशासन ने शहर के हर चौराहे, हर गली पर कैमरे लगाए, जिनका उद्देश्य हर तरह के अपराध, गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। समाज में एक जैसे गया सरकार, शासन और प्रशासन की इन कैमरों के माध्यम से शहर के चप्पे चप्पे पर निगाह है। कोई भी, कितना भी शांतिर क्यो ना हो वह इस आसमानी दृष्टि से बच नहीं सकता। कुल मिलाकर शहर भर में दौड़ रहा ट्रैफिक और प्रत्येक वाहन पर नजर रखने की पुख्ता व्यवस्था इन कैमरों के माध्यम से की गई। कोरोना काल के समय शासन के आदेश से ऑफलाइन चालान की व्यवस्था खत्म कर दी गई मैन्युअल चालान बंद हो गए। ऑनलाइन चालान होने लगे। तकनीक के इस्तेमाल से ट्रैफिक पुलिस को किसी से भी कागज मांगने की आवश्यकता ही खत्म हो गई। गाड़ी का नंबर डालते ही गाड़ी से संबंधित समस्त जानकारी एक विलक पर सामने उपलब्ध होने लगी। लेकिन बेतरतीब ढंग से चलने वाले, नियमों की अनदेखी करने वाले और ओवरलोडिंग वाहन चलाने वालों के लिए स्थितियां दुरुह हो गईं।

मैन्युअल चालान के समय कुछ ले देकर बच निकलने वाली जुगत खत्म हुई तो वाहन मालिकों ने बच निकलने का दूसरा नायाब तरीका तलाश लिया। शहर के अंदर दौड़ रहे ऑटो, विक्रम ई रिक्शा हों या हाईवे पर दौड़ रहे ट्रक, डंपर हों यकायक सभी से नंबर प्लेट या तो गायब होने लगी या फिर एन केन प्रकारेण नंबर को छुपाने की जुगत शुरू हो गई। ट्रैक्टर और ट्राली, टैंकर वाले तो पहले से ही नियमों को अनदेखा करते आ रहे थे।

कानपुर नगर से होकर गुजरने वाले हमीरपुर रोड पर ही यदि आप निगाह डालें तो किसी भी समय औसतन तीन में से दो ट्रक और डंपर में नंबर प्लेट या तो नदारत मिलेगी या उसे पर पेंट, कालिख वगैरह लगाकर उसे अपठनीय बना दिया गया होगा। हद तो यह है की बड़ी संख्या में डंपर और ट्रक आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आगे पीछे दोनों तरफ नंबर प्लेट नहीं नजर आएगी। हमीरपुर रोड भारी वाहनों के यातायात की दृष्टि से अति व्यस्त हाईवे है। हमीरपुर, सागर, कर्वी, बांदा से मौरंग और गिद्धी ढुलाई सबसे अधिक इसी मार्ग से होती है और इसी मार्ग पर सबसे अधिक दुर्घटनाओं का जोखिम भी रहता है। ट्रक और डंपर ड्राइवर द्वारा सबसे पहले पहुंचने की जद्दोजहद और सबसे आगे रहने की सनक के चलते भारी भार वाहनों की अनियंत्रित गति इस मार्ग को दुर्घटना बाहुल्य बना देती है।

प्रश्न यह उठता है कि आरटीओ प्रशासन हो या ट्रैफिक पुलिस क्या इन विभागों को वाहन चालकों

## डीएम के आदेश आरटीओ अफसरों के ढेंगे पर

- » शहर और जिले के आसपास में बिना नंबर प्लेट वाहनों की भरमार
- » हमीरपुर रोड में गुजर रहे औसतन हर तीसरे ट्रक, डंपर की नंबर प्लेट गायब
- » जिले में आरटीओ की कार्यवाही ऊंट के मुंह में जीरा की तरह



## खबर छपने पर एक-दो दिन कार्रवाई का दिखावा...

आरटीओ हो या ट्रैफिक पुलिस बिना नंबर प्लेट वाहनों के सामने बेबस ही नजर आ रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है कानपुर नगर में बिना नंबर प्लेट चलते यह वाहन आम लोगों, पत्रकारों को तो दिख जाते हैं परंतु इन दोनों जिम्मेदार विभागों को नहीं दिखते हैं। जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा बुलाई गई बैठक में आरटीओ प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि अप्रैल माह में 315 ओवरलोड वाहनों के चालान किए गए। चालान की यह संख्या ही बताती है कि आरटीओ प्रशासन कितनी गंभीरता से ओवरलोड व बिना नंबर प्लेट वाहनों पर कितनी शिद्दत से कार्रवाई कर रहा है! हालात ये हैं अखबारों में खबर छपने के बाद आरटीओ विभाग अगले एक-दो दिन तो चुस्त-दुरुस्त, मुस्तैद नजर आता है लेकिन उसके बाद फिर वही पुराना ढर्रा चालू हो जाता है।

द्वारा कैमरे से बचने के इस खेल की जानकारी नहीं है। यदि इन विभागों को वाहन मालिकों द्वारा नंबर प्लेट गायब करने यहां टेंपर्ड करने के इस खेल की जानकारी है तो उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? या फिर सरकार और शासन की मंशा के विपरीत कोई खेल चल रहा है! पिछले दिनों जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह ने आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक में निर्देश दिए थे कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन यदि आप शहर के



### कहीं कोई खेल तो नहीं....

दरअसल शहर की सड़कों पर दौड़ रहे बिना नंबर प्लेट के डंपर और ट्रकों पर मोटे-मोटे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे शब्द यह आशंका उत्पन्न कर रहे हैं कि कहीं आरटीओ विभाग में बिना नंबर प्लेट वाहनों को चलाने का कोई खेल तो नहीं चल रहा है? अधिकांश बिना नंबर प्लेट वाहनों में ठाकुर साहब, भदौरिया, कोर बी जैसे शब्द बहुत बोल्ड करके लिखे दिखते हैं।

हाईवे पर नजर दौड़ाए तो आपको आभास होगा जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है।

# खबर का असर: गांव में पहुंचा जल जीवन मिशन से पानी

» स्वराज इंडिया की खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन, तेजी से हुई मरम्मत, पानी पहुंचा गांव-गांव

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**  
**कानपुर देहात ।** मलासा ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाखों रुपये खर्च करके पानी की टंकी तो बना दी गई, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते वह ग्रामीणों के किसी काम नहीं आ रही थी। बीते कुछ दिनों में आए तेज आंधी-तूफान के बाद गांव की जल आपूर्ति पूरी तरह टप हो गई थी। पानी की लाइन में गंभीर खराबी आ गई थी, जिससे टंकी से पानी का वितरण पूरी तरह से बंद हो गया था। गांव के लगभग 3500 से अधिक की आबादी को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा था।

कई पुराने हैंडपंप भी लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण अब गंदा और दूषित पानी उगलने लगे थे। ग्रामीणों की पीड़ा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर आंख मूंदे बैठे थे।

## जल जीवन मिशन फेल: 3500 की आबादी पानी को तरस रही

» मलासा गांव की टंकी बनी सफेद हाथी, तीन दिन से बंद पड़ी जल आपूर्ति, अधिकारी बेपरवाह

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो  
**कानपुर देहात ।** मलासा गांव में जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी तकनीकी खामियों के कारण ग्रामीणों के किसी काम नहीं आ रही। बीते तीन दिनों से अधिक समय से जल आपूर्ति पूरी तरह टप रही है। पानी की लाइन में गंभीर खराबी के चलते टंकी से जल वितरण बंद हो गया है। खलत यह है कि जिन हैंडपंपों को लोगों को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया, वे भी अब खराब हो चुके हैं।

सरकार की मंशा थी कि जल जीवन मिशन से हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचे, लेकिन योजना का क्रियान्वयन इतना लचर है कि अब गांव में पानी की रालाय में भटकना शुरू हो गया है। विभागीय अधिकारी कोठे पर निरीक्षण तक करने नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में राग भरना जा रहा है।

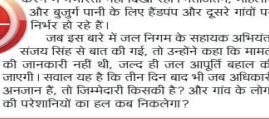
**जिम्मेदारों की अनदेखी, गांव में गंदा खराब**  
गांववालों का कहना है कि अगर अधिकारी समय रहते



पानी की टंकी और पाइपलाइन की जांच करते तो यह संकट पैदा नहीं होता।



जोकिन आज भी विभाग तकनीकी खामियों को ठीक करने में गंभीरता नहीं दिखा रहा। नतीजतन, महिलाएं और बुजुर्ग पानी के लिए हैंडपंप और दूसरे गांवों पर निर्भर हो रहे हैं।



जब इस बारे में जल निगम के सहायक अभियंता संजय सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी नहीं थी, जल्द ही जल आपूर्ति बहाल की जाएगी। खलत यह है कि तीन दिन बाद भी जब अधिकारी अनजान हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? और गांव के लोगों की परेशानियों का हल कब निकलेगा?

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सनदी देवी द्वारा निर्मित डिजिटल 127/875, संचालन नगर, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनुर कुमार, FNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swrajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, Website: www.swrajindianews.com | (समस्त खबर-विचार कानपुर नगरवालय के अर्धीन होंगे)

गांव की इस गंभीर समस्या को स्वराज इंडिया के जिला संवाददाता शंकर सिंह ने प्रमुखता से उठाया और जमीनी हकीकत को समाचार के माध्यम से सामने रखा।

खबर प्रकाशित होते ही जल निगम के सहायक अभियंता संजय सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और लापरवाह तंत्र को चेतावनी देते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

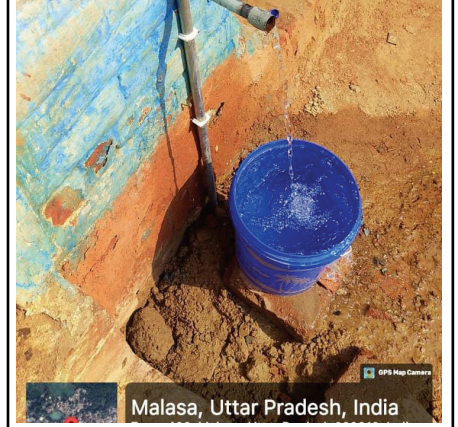
ठेकेदार और अवर अभियंता अंकिता सिंह को तुरंत गांव भेजा गया, जहां उन्होंने खराब

पड़ी पाइपलाइन की मरम्मत शुरू करवाई। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई का असर यह हुआ कि अगले ही दिन गांव में दोबारा पानी की सप्लाई शुरू हो गई।

ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और बताया कि अब हमारे घरों में नल से पानी आ रहा है। पहले बहुत परेशानी हो रही थी। सहायक अभियंता ने जानकारी दी कि शेष बचे कुछ घरों में भी जल्द कनेक्शन करवा कर नियमित जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी।



Malasa, Uttar Pradesh, India  
7wcp+Jcr, Malasa, Uttar Pradesh 209312, India  
Lat 26.272975° Long 79.835834°  
21/05/2025 10:04 AM GMT +05:30



Malasa, Uttar Pradesh, India

# सात दिवसीय श्री राम कथा शुरू



**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**  
**सूरतगंज( बाराबंकी) ।** रविवार को विहिप बजरंगदल के अगुवाई में दुर्गापुर नौबस्ता में सात दिवसीय श्री राम कथा संजीत कुमार सिंह द्वारा आयोजित की जा रही है जिसके उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई इस यात्रा में सैकड़ों ग्राम वासियों ने हिस्सा लिया। यह कलश यात्रा दुर्गापुर नौबस्ता से शुरू हुई सुमली

नदी पहुंची जहां पर कलश में जल भर पुनः गांव पहुंची। जहां पर अयोध्या धाम से पधारी कथावाचिका अनुराधा सरस्वती जी अपने मुखार बिंदु से सात दिवसीय संगीतमयी श्री राम कथा की अमृत वर्षा का शुभारंभ करेंगी। इस मौके पर पारुल सिंह अमित सिंह राठौर जिला सह संयोजक बजरंगदल चंदन सिंह रैकवार, सुरेंद्र गोस्वामी, विहिप अध्यक्ष सूरतगंज मूल चंद्र मिश्रा प्रखंड संयोजक बजरंगदल अनुपम वर्मा रंजीत सिंह मनोज कुमार सिंह प्रांशु सिंह सहित समस्त ग्राम वासियों उपस्थित रहे।

# डीएम और एसपी ने जिला कारागार में किया निरीक्षण



**स्वराज इंडिया संवाददाता**  
बाराबंकी। जिलाधिकारी शंशाक त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस बल के साथ जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरकों, मेस, जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे, वीडियो कान्फेंसिंग रूम आदि की सघन चेकिंग की गई। तदोपरांत कैदियों की समस्याओं/सुविधाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित से जानकारी ली गई। तथा साफ-सफाई आदि के सम्बन्ध में कारागार कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये तथा बन्दिनों से मिलने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी की गई।

**सार्वजनिक नोटिस**  
थाना बिल्हौर पर पंजीकृत मु0अ0स0 134/2024 धारा 394 भादवि0 मे वाचित अभियुक्त दिलीप उर्फ खलीफा पुत्र सीताराम निवासी भगतसिंह नगर थाना बिल्हौर कानपुर नगर के विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 82 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही कर डुगडुगी बजवाई गई व लाउड स्पीकर से मुनादी की कार्यवाही की गई। अन्तर्गत धारा 82 सी0आर0पी0सी0 की नोटिस की प्रति अभियुक्त के घर के दरवाजे पर चप्पा की गई तथा दिखायी देने वाले स्थानों पर व आसपास के अन्य गौडगाड़ वाले स्थानों पर चप्पा की गई।  
**आज्ञा से कोतवाली प्रभारी बिल्हौर, कानपुर नगर।**

# सीएमओ कार्यालय की कृपा से गली कूचों में अवैध निजी नर्सिंग होम

» बिना लाइसेंस, बिना डाक्टर चल रहे कई ऑपरेशन थियेटर

» अवैध अस्पतालों पर सीएमओ का शिकंजा, हिल गए नर्सिंग होम माफिया

**स्वराज इंडिया संवाददाता अयोध्या।** गली-कूचों से लेकर रिहायशी कॉलोनियों तक चल रहे अवैध नर्सिंग होम वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ करते आ रहे हैं। शिकायतें होती रहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कुंमकर्णी नींद तक नहीं खुली जब तक कि कुछ दर्दनाक हादसों ने पूरे सिस्टम को झकझोर नहीं दिया। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. सुशील कुमार बनियान की अग्रुवाई में जिले में अवैध अस्पतालों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है। इस कार्रवाई से आम लोगों में एक नई उम्मीद जगी है लेकिन इसके बाद भी सुधार नहीं है।



सेपटी है और न ही एंबुलेंस की सुविधा। इन अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों का कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं होता, केवल ऑपरेशन के समय बाहर से विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं।

### दलालों के जाल में फंसे हैं मरीज

सरकारी अस्पतालों के बाहर इन अवैध नर्सिंग होम के दलाल तैनात रहते हैं। यह मरीजों को बहला-फुसलाकर मोटे कमीशन के लालच में उन्हें ऐसे अस्पतालों तक पहुंचाते हैं, जहां गलत इलाज या गलत ऑपरेशन से उनकी जान तक चली जाती है।

कई हाई प्रोफाइल मामलों में ही जांच होती है, बाकी शिकायतें दबा दी जाती हैं।

जांच की आड़ में फाइलें होती रहीं बंद स्वास्थ्य विभाग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक ज्यादातर शिकायतों में केवल



### सीएमओ का बयान

अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम और क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ शिकायत कर सकता है, और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

डॉ. सुशील कुमार बनियान, सीएमओ

### अवैध नर्सिंग होम की काली करतूतें

1. नाका में फिजिशियन ने किया ऑपरेशन, जच्चा-बच्चा की मौत  
नाका क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में दो अक्टूबर 2022 को गीता कनौजिया और उनके नवजात की सिजेरियन डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। जांच में सामने आया कि अस्पताल का पंजीकरण नहीं था और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर केवल फिजिशियन के रूप में पंजीकृत था। मामला तूल पकड़ने पर जांच हुई लेकिन उसके बाद कार्रवाई उठे बस्ते में चली गई।

2. इंजेक्शन से गई बच्चे की जान  
जुलाई 2024 में खंडासा क्षेत्र के मखौली चौराहे पर स्थित एक

औपचारिक जांच की गई और बाद में फाइलें बंद कर दी गईं। अब जब सीएमओ ने खुद मोर्चा



अवैध क्लिनिक में इलाज के दौरान छह साल के शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर के लगाए इंजेक्शन से उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। पुलिस ने डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया।

3. सर्जन न होने के बावजूद हुआ ऑपरेशन, फिर मौत

बीकापुर के अमित कुमार की पत्नी महिमा का देवकाली के एक नर्सिंग होम में सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि अस्पताल में कोई अधिकृत सर्जन नहीं था। तत्कालीन सीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया था।

### जनता की उम्मीदें जागीं, निगरानी जरूरी

इन घटनाओं ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को कठघरे में खड़ा किया, बल्कि यह सवाल भी उठाना कि कितनी और जानें जाने के बाद सिस्टम जागेगा? फिलहाल सीएमओ की पहल से कुछ उम्मीदें जागी हैं, लेकिन यह कार्रवाई तभी असरदार होगी जब निगरानी और जवाबदेही लगातार बनी रहे।

संभाला है तो कार्रवाई की सुगबुगाहट लोगों में चर्चा का विषय बन गई है।

# विकासखंड मया में पारदर्शिता की उड़ती धज्जियां

» विकास के संरक्षण में विकासखंड मया में भ्रष्टाचार का विकास

» विकास के आड़ में भ्रष्टाचार प्रधान-सचिव की मिलीभगत उजागर

» दलपतपुर का बिल, मया भीखी में भुगतान- ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर खेला गया घोटाले का खेल

**स्वराज इंडिया संवाददाता अयोध्या।** विकासखंड मयाबाजार में पारदर्शिता को लगा ग्राहण एक सड़क, का दोबार भुगतान - ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर खेला गया लाखों का घोटाला जनपद अयोध्या के विकासखंड मया बाजार की ग्राम पंचायत मया भीखी भ्रष्टाचार के दलदल में गहराई तक धँसी प्रतीत हो रही है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, जिसे पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए विकसित किया गया था, उसी का सहारा लेकर सरकारी धन की दोहरी बंदरबान्त की जा रही है।

ताजा मामला मया भीखी गांव में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के

| Payment Voucher Detail                        |   |                 |   |
|---|---|-----------------|---|
| Financial Year: 2024-2025                     |   |                 |   |
| Month: February                               |   |                 |   |
| State: UTTAR PRADESH                          |   |                 |   |
| Zilla Panchayat and Equivalent: Ayodhya       |   |                 |   |
| Block Panchayat and Equivalent: Maya Bazar    |   |                 |   |
| Village Panchayat and Equivalent: Maya Bhothi |   |                 |   |
| Type of Transaction                           | Expenditure                               | Activity Code   | 55179779  |
|   |   |                 | Interlocking on power house building Tak Interlocking (2021-2022) |
| Scheme Name                                   | XV Finance Commission-Basic Grant (Contd) |                 |   |
| Voucher Date                                  | 11/02/2025                                | Voucher No      | XVFC/2024-25/P/49   |
| Account Head                                  | Expenditure Heads                         | Amount (in Rs.) | 54,332  |
|   | 5054 - Capital Outlay on Transportation   |                 |   |
|   | 302 - Construction of Culvert/Bridge      |                 |   |
|   | 02 - Wages                                |                 |   |
| Particulars                                   | Payment for material                      | Attached File   | 1739245780542-100790.jpeg   |
| Mode of Payment                               | Details                                   | To Whom Paid    | Amount (in Rs.)   |
| PFMS  | Account Type: Bank                        | VERSHA TRADERS  | 40,052  |
|   | Account No.:*****G676                     |                 |   |
| PFMS  | Account Type: Bank                        | VERSHA TRADERS  | 54,380  |
|   | Account No.:*****G676                     |                 |   |

फरवरी माह में पोर्टल पर अपलोड किए गए भुगतान वाउचर में कई चौकाने वाली विसंगतियाँ उजागर हुई हैं। एक ही कार्य - इंटरलॉकिंग से पावर हाउस बिल्डिंग तक सड़क निर्माण (2021-2022) - के लिए वर्षा ट्रेडर्स को दोबार भुगतान किया गया- 40,052 और 54,280 कुल ?94,332, जबकि बिल पर 10,07,900 है। दूसरा मामला ?65,950 का श्री अम्बे ट्रेडर्स, अलनाभारी, मया बाजार के नाम जारी चालान संख्या 398 में की राशि दर्ज है, जबकि यह कार्य किसी अन्य पंचायत दलपतपुर का बताया गया है। मजे की बात यह कि इस बिल को भी

| Payment Voucher Detail                        |   |                 |   |
|---|---|-----------------|---|
| Financial Year: 2024-2025                     |   |                 |   |
| Month: February                               |   |                 |   |
| State: UTTAR PRADESH                          |   |                 |   |
| Zilla Panchayat and Equivalent: Ayodhya       |   |                 |   |
| Block Panchayat and Equivalent: Maya Bazar    |   |                 |   |
| Village Panchayat and Equivalent: Maya Bhothi |   |                 |   |
| Type of Transaction                           | Expenditure                               | Activity Code   | 501070  |
|   |   |                 | Interlocking on power house building Tak Interlocking (2021-2022) |
| Scheme Name                                   | XV Finance Commission-Basic Grant (Contd) |                 |   |
| Voucher Date                                  | 11/02/2025                                | Voucher No      | XVFC/2024-25/P/49   |
| Account Head                                  | Expenditure Heads                         | Amount (in Rs.) | 4,132   |
|   | 5054 - Capital Outlay on Transportation   |                 |   |
|   | 302 - Construction of Culvert/Bridge      |                 |   |
|   | 02 - Wages                                |                 |   |
| Particulars                                   | Payment for material                      | Attached File   | 1739245780542-100790.jpeg   |
| Mode of Payment                               | Details                                   | To Whom Paid    | Amount (in Rs.)   |
| PFMS  | Account Type: Bank                        | VERSHA TRADERS  | 4,052   |
|   | Account No.:*****G676                     |                 |   |
| PFMS  | Account Type: Bank                        | VERSHA TRADERS  | 54,380  |
|   | Account No.:*****G676                     |                 |   |

मया भीखी ग्राम पंचायत में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल अपलोड कर दिया गया, जिसमें दलपतपुर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर स्पष्ट हैं। इसी प्रकार, उदय कंस्ट्रक्शन और जनरल ऑर्डर सप्लायर्स, तेजापुर अंकारीपुर के नाम चालान संख्या 120 के अनुसार 54,758 का भुगतान होना था, जबकि पोर्टल पर यह राशि वर्षा ट्रेडर्स के खाते में ट्रांसफर दिखाई गई है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मया विकासखंड में एक ही कार्य के लिए अलग-अलग योजनाओं (राज्य वित्त एवं मनरेगा) से दोहरी फंडिंग कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। सवाल के घेरे में ग्राम प्रधान और सचिव

मया ब्लाक के खंड विकास अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया की प्रकरण सज्ञान में है जांच समिति गठित कर जांच की जाएगी और स्पष्टीकरण प्रधान और सचिव से मांगा जाएगा। जबकि डीसी मनरेगा सविता सिंह ने बताया अभी मामला सज्ञान में नहीं आया है। जानकारी करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

पंचायती राज मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस नीति और डिजिटल सिग्नेचर व्यवस्था के बावजूद, प्रधान-सचिव की मिलीभगत से यह खेल खेला गया। इससे न सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, बल्कि ई-गवर्नेंस की साख पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कहती है सरकार की मंशा? ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की स्थापना पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता और जवाबदेही के लिए की गई थी। लेकिन यदि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग ही हेराफेरी के लिए किया जाने लगे तो सरकार की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या होगी कार्यवाही? अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर शिकंजा कसेगा या यह भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा?

# ‘बाबू तुम्हारा नहीं हो सका तो किसी और का भी नहीं होऊंगा’

» हाल ही में युवक की हुई थी शादी, युवक ने नोट लिख कर किया सुसाइड

स्वराज इंडिया संवाददाता

**बाराबंकी।** एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है युवक की हाल ही में शादी हुई है उसका एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रहा है। इसमें उसने प्रेम संबंध का जिक्र किया है। पुलिस जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या परिजनों ने प्रधान और उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। सत्यम बीजेपी से जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। यहां एक युवक का शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला है। इस युवक की हाल ही में शादी हुई थी। इस घटना से जुड़ा एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रहा है। इसमें युवक ने लिखा है कि ‘बाबू तुम्हारा नहीं हो सका तो किसी और का भी नहीं होऊंगा’। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम संबंध से जुड़ा है।



बाराबंकी के रामसनेहीघाट का है। यहां रहने वाले युवक सत्यम मिश्रा का शव सकौली की सरहद के पास बाग में पेड़ से लटका मिला है। शनिवार की शाम को वह घर से शौच के लिए निकला था। देर रात तक वह घर नहीं लौटा और रविवार की

सुबह उसका शव सदिग्ध परिस्थिति में पेड़ से लटका पाया गया। सत्यम के परिजनों के मुताबिक उसका प्रेम संबंध चल रहा था। इसी प्रेम संबंध की वजह से गांव के प्रधान आशीष मिश्रा और उनकी पत्नी भावना मिश्रा ने सत्यम की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया है।

**सोशल मीडिया पोस्ट ने दिया नया मोड़** -पुलिस की जांच के दौरान ही सत्यम के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने घटना को नया मोड़ दे दिया है। इस पोस्ट में सत्यम ने तक तस्वीर अपलोड किया है। इस तस्वीर के साथ लिखा है कि बाबू तुम्हारा नहीं हो सका तो किसी और का भी नहीं होऊंगा। पुलिस के मुताबिक हाल ही में युवक की शादी हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपनी शादी से खुश नहीं था। उसने अपने परिजनों के दबाव में शादी तो कर ली, लेकिन अपनी प्रेमिका को भुला नहीं पाया। इसलिए उसने गिल्टी फिल करते हुए सुसाइड किया है।

**बीजेपी से जुड़ा था सत्यम** -सत्यम मिश्रा के परिजनों के मुताबिक वह बीजेपी से जुड़ा था। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा के साथ तस्वीर लगी मिली है। बताया जा रहा है कि वह बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेता था। हालांकि शादी के बाद से उसकी सक्रियता थोड़ी कम हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में यह तय करना बड़ी चुनौती है कि सत्यम की हत्या हुई या मामला सुसाइड का है। फिलहाल पुलिस तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

## पेस्टीसाइड दुकानदार की हथगोला मारकर हत्या

» पुलिस ने सात नामजद सहित कई अज्ञात हमलावरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया

स्वराज इंडिया संवाददाता

**सूरतगंज(बाराबंकी)।** मोहम्मदपुर खाला थाना इलाके के गोड़ा में शनिवार देरशाम रजिशा में पेस्टीसाइड के दुकानदार पर हमलावरों ने हथगोले से हत्या कर दी थी। पुलिस ने सात नामजद सहित कई अज्ञात हमलावरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। कि रविवार दोपहर पोस्टमार्टम उपरांत घर पहुंचे शव का परिजनों ने गोड़ा-भैरमपुर मार्ग पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और सभी की गिरफ्तारी व घर पर बोल्टोजर चलाने की मांग करने लगे करीब दो घण्टे से चले रहे प्रदर्शन को अपर पुलिस अधीक्षक के अवशासन पर समाप्त हुआ। एएसपी ने बताया मामले में तीन नामजद व पांच अज्ञात को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है शेष की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।



गोड़ा गांव निवासी नरेंद्र मौर्या चौराहे पर स्थित हाइवेयर की दुकान चलाता है उसी के बगल में भतीजे शैलेन्द्र मौर्या की पेस्टीसाइड की दुकान है। शनिवार को चाचा भतीजे अपनी-अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी देरशाम गांव के देशराज, गुड्डू, सुनील, बघेल, मनीष, राहुल आदि लोगो ने रजिशा में हथगोले से हमला बोल दिया हमले में शैलेन्द्र गम्भीर रूप से घायल हो गया जबकि चाचा नरेंद्र किसी तरह से दुकान की गैलरी में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर जान बचाई इस दौरान हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए कई फायरिंग और पेस्टी साइड की दुकान को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। सूचना पर करीब एक घंटा देर से पहुंची पुलिस ने शैलेन्द्र को सीएचसी सूरतगंज ले गई वहा चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर सीएचसी में हंगामा शुरू कर दिया। तीन घण्टे चले हंगामे के बाद सीओ जगताराम कनौजिया के आश्वासन पर परिजन शव पीएम कराने को राजी हुए। पुलिस ने नरेंद्र की तहरीर सात नामजद व

कई अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव पीएम के लिए भेज दिया। रविवार दोपहर पीएम उपरांत घर पहुंचे शव को परिवारजनों ने गोड़ा भैरमपुर मार्ग पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और सभी आरोपितों की गिरफ्तारी व घर पर बुल्टोजर चलाने की मांग करने लगे पुलिस के काफी समझाने के बाद भी परिजन शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चन्द्र त्रिपाठी के आश्वासन के बाद परिजन

माने और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपना बेटा और भाई खोया है। एक दुधमुही बच्ची के पिता का साया उसके सिर से उठ गया है। शेष की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं जल्द गिरफ्तार में होंगे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्या, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शेखर हयारण, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।

# गोंडा बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप पर होगी कार्रवाई

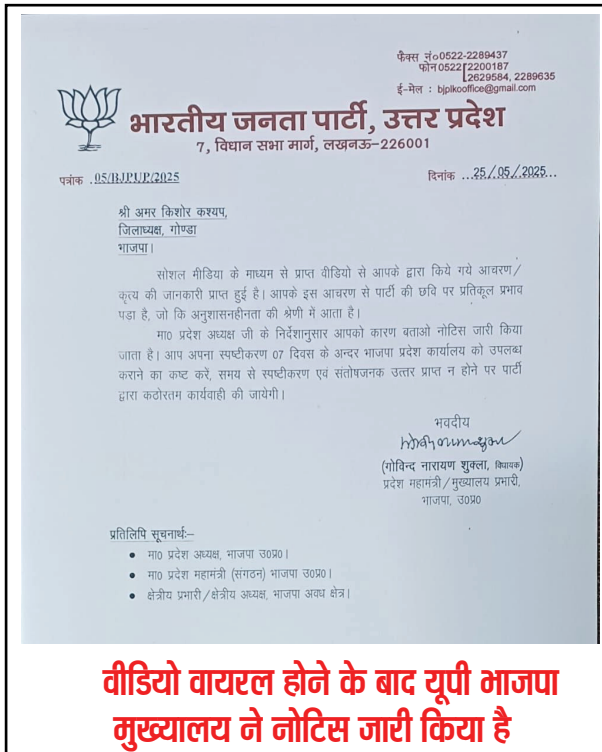
» पार्टी ने जिलाध्यक्ष को भेजा कारण बताओ नोटिस, पार्टी कार्यालय में आपत्तिजनक वायरल वीडियो से मचा बवाल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के बीजेपी

जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप बमबम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमर किशोर कश्यप को एक अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जल्द ही उन पर एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक युवती के साथ पार्टी कार्यालय में अश्लील हरकत करते दिख रहे हैं।

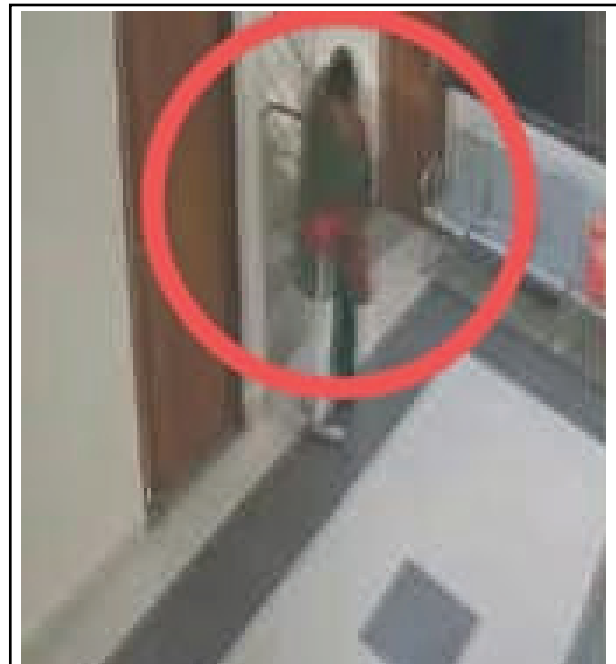
पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी गोविन्द नारायण शुक्ला की ओर से भेजी गई नोटिस में कहा गया है कि अमर किशोर कश्यप के आचरण से पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर उन्हें 7 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण बीजेपी प्रदेश कार्यालय को भेजने के लिए कहा गया है। समय पर स्पष्टीकरण नहीं देने या जवाब असंतोषजनक होने पर कठोरतम कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।



वीडियो वायरल होने के बाद यूपी भाजपा मुख्यालय ने नोटिस जारी किया है

वायरल वीडियो में क्या है?

12 अप्रैल 2025 की रात का बताया जा रहा यह वीडियो पार्टी कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज का है। पहले वीडियो में एक व्यक्ति रात 9-35 बजे कार्यालय



युवती के साथ इस तरह से चिपके नजर आ रहे बीजेपी जिला अध्यक्ष

का गेट खोलता हुआ दिखाई देता है, और कुछ देर बातचीत के बाद एक युवती को इशारे से अंदर बुलाता है। दूसरे वीडियो में रात 9-39 बजे वही युवती एक बैग लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है और उसके पीछे जिलाध्यक्ष दिखाई देते हैं, जो युवती को सहारा देते और बाहों में भरते नजर आते हैं। यह दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

## 30 मई को पीएम का आगमन, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण

» पीएम मोदी कानपुर में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास



स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शहर पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी ने पीएम की जनसभा तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी की 30 की महानगर यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी उप्र प्रशांत कुमार कानपुर पहुंचे। सबसे पहले वह पीएम के सभा



स्थल सीएसए पहुंचे, जहां तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा रूट व्यवस्था, हैलीपैड, जनसभा स्थल एवं पार्किंग स्थलों का जायजा किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए, जिससे कार्यक्रम के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जा सकें।

## भारतीय मौसम विभाग का दक्षिण भारत के तीन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के तीन राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इन राज्यों में 26 मई को भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है।

साथ ही मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए गंभीर हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। और वहीं, बिहार, मध्य

प्रदेश और महाराष्ट्र में भी तेज हवा के साथ बारिश की बात कही गई है। इसके अलावा आईएमडी की ओर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ और भागों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं।

